(c) the steps taken by Government to accelerate growth rate of industrial sector especially capital goods sector?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) Sectorwise growth rate targets for industrial production are not fixed by the Government. A statement showing details of sector wise rate of growth of index of industrial production achieved during the last 5 years is enclosed. (See below).

(b) The performance of the industrial sector during the last 3 years was effected by demand constraints in general, tight credit policy and short term impact of stabilisation measures adopted in the wake of severe balance of payment crisis during 1990-91.

(c) The policy initiatives taken in the new industrial policy in July 1991, the trade policy and supporting fiscal and monetary measures announced in the subsequent budgets are all aimed at accelerating the growth of industrial production. The extension of MODVAT for the capital goods and imposition of countervaling duty on import of capital goods would help the indigenous industry.

Statement

Sectorwise growth rates of Index of Industrial Production (Percent)

Sector	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
Manufacturing	8.6	8.9	—0.8	2.1	2.2
Mining & Quarrying	6.3	4.5	0.6	0.5	2.5
Electricity	10.9	7.8	8.5	5.0	7.3
Overall	8.6	8.3	0.6	2.3	3.0

Source :—Central statistical organisation.

औद्योगिक उत्पादन विकास दर

2387. **श्री सोमपाल :**
श्री शारदा महन्ती :
डा० बापू कालदाते :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान अब तक औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर कितनी रही है और पूरे वर्ष के दौरान औसत उत्पादन वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ;

(ग) औद्योगिक उत्पादन में उतार-चढ़ाव में विभिन्न उद्योगों ने कितना-कितना सकारात्मक अथवा नकारात्मक योगदान दिया और उसके विस्तृत कारण क्या हैं ; और

(घ) सरकार ने उन क्षेत्रों को, जिनमें गत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक उत्पादन कम रहा है, को बढ़ावा देने एवं उनका उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या विशेष कदम उठाये हैं और अब तक उनके क्या परिणाम सामने आये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी औद्योगिक उत्पादन के अनुमानों के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र ने 1993–94 में 3.0% विकास दर दिखाई है ।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की विकास दर निम्नलिखित है:-

विकास-दर (प्रतिशत में)

1991–92	1992–93	1993–94
0.6	2.3	3.0

(ग) विनिर्माणकारी क्षेत्र के अन्तर्गत 17 विशद उद्योग समूहों में से 1993–94 के दौरान 64.3% योगदान करने वाले 13 उद्योग समूहों ने सकारात्मक विकास दर दर्शाई है, जबकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 12.8% योगदान करने वाले 4 उद्योग समूहों ने उत्पादन में कमी दर्शाई है। मांग संबंधी बाधाओं, कड़ी वित्तीय और 1990–91 में अपनाये गये स्थिरीकरण संबंधी उपायों के अल्प कालिक प्रभाव के कारण औद्योगिक क्षेत्र का कार्य निष्पादन प्रभावित हुआ था।

(घ) जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति में किये गये नीति संबंधी उपायों, बाद के बजटों में घोषित सहायक राजकोषीय और वित्तीय उपायों का उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन के विकास की गति को तीव्र करना है। पूंजीगत वस्तुओं के लिये मोडवेट को लागू करने तथा पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर समतुल्य शुल्क लगाये जाने से स्वदेशी उद्योग को मदद मिलेगी।

मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास केन्द्रों की स्थापना

2388. **श्री कैलाश नारायण सारंग :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सरकार की औद्योगिक विकास केन्द्रों की स्थापना संबंधी नीति के अन्तर्गत 30 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश से स्थापित किये जाने वाले आठ विकास केन्द्रों के लिये वित्तीय व्यवस्था के अन्तर्गत क्या केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा अंश-पूंजी तथा ऋण-राशि विमुक्त कर दी गई है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस संबंध में मध्य प्रदेश को क्रियान्वयन एजेंसी (औद्योगिक केन्द्र विकास निगम) द्वारा कोई आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों को आवश्यक निर्देश जारी किये हैं तथा क्या योजना क्रियान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश के लिये और अतिरिक्त विकास केन्द्रों को स्वीकृत करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) तथा (ख) मध्य प्रदेश में विकास केन्द्रों के लिये वित्तीय संस्थानों ने अब तक अपनी अंश-पूंजी जारी नहीं की है। किन्तु मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम ने धन जारी करने के लिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को अनुरोध प्रस्तुत किया है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इन परियोजनाओं की जीव्यक्षमता का मूल्यांकन कर रहा है।

(ग) केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों को इस योजना के अधीन अपनी अनुपाति अंश पूंजी जारी करने की सलाह दी गई है। योजना के कार्यन्वयन की निरन्तर समीक्षा की जा रही है।

(घ) जी, नहीं।